भारत में अवैध व्यापार

प्रलिमिस के लयि:

भारत में अवैध व्यापार, फकि्की कैस्केड, अवैध बाज़ार, वतित्तीय प्रवाह, संगठति अपराध और आतंकवाद, धन शोधन, रेड सैंडरस, GDP (सकल घरेलू उत्पाद) ।

मेन्स के लयि:

भारत में अवैध व्यापार और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव ।

स्रोत : इंडयिन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

फकि्की कैस्केड/FICCI CASCADE द्वारा **'हडिन स्ट्रीम्स: लकिेज बटिवीन इलसिटि मार्केट्स, फाइनेंशयिल फ्लो, ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड टेरेरज़िम'** शीर्षक से जारी एक रपिोर्ट के अनुसार, भारत में अवैध अर्थव्यवस्था का 1-10 के पैमाने पर कुल स्कोर **6.3 है, जो अन्य 122 देशों में से 5 के औसत स्कोर से अधकि है,** जो एक बड़ी अवैध अर्थव्यवस्था का संकेत देता है ।

फकि्की कैस्केड:

- फकि्की कैस्केड/FICCI CASCADE (अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाली तस्करी और जालसाज़ी गतविधियों के खलिाफ फकि्की की समतिि), **भारतीय वाणज्यि एवं उद्योग महासंघ (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry- FICCI) की एक पहल है ।**
- इसकी स्थापना 18 जनवरी, 2011 को भारत और वशि्व स्तर पर **जाली, पास-ऑफ एवं तस्करी के सामानों के अवैध व्यापार के गंभीर मुद्दे** को उजागर करने हेतु की गई थी ।

अवैध व्यापार:

- अवैध व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं एवं सेवाओं के अवैध आदान-प्रदान से है जो सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय नकिायों द्वारा स्थापति कानूनों, वनियिमों या नयिंत्रणों का अनुपालन नहीं करता है ।
- **ये गतविधियिाँ कानूनी ढाँचे के बाहर होती हैं** और इनमें अक्सर वभिनि्न प्रकार की **प्रतबिंधति सामग्री, जालसाज़ी, चोरी, तस्करी, कर चोरी,** धन शोधन **एवं अन्य अवैध** गतविधियिाँ शामलि होती हैं ।

रपिोर्ट के मुख्य तथ्य:

- **भारत में अवैध व्यापार का अवलोकन:**
    - 2022-23 के वतित्तीय वर्ष में 3.5 टन सोना, 18 करोड़ सगिरेट स्टकि्स, 140 मीट्रकि टन रेड सैंडरस और 90 टन हेरोइन ज़ब्त की गई ।
        - 122 देशों के औसत स्कोर 5.2 की तुलना में भारत का स्कोर 4.3 काफी कम है, जो **संगठति अपराध अभकिर्त्ताओं की कम भागीदारी** लेकनि आपराधकि नेटवर्क के महत्त्वपूर्ण प्रभाव का सुझाव देता है ।
- **भारत में अवैध वतित्तीय प्रवाह:**
    - **वैल्यू गैप इंडयिा (2009-2018):**
        - वर्ष 2009-2018 के दौरान **अवैध आयात और नरि्यात चालान के परणािमस्वरूप भारत को संभावति राजस्व में कुल 13**

बलियिन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ।
  - असंगृहीत मूल्य वर्धति कर (VAT) की राशि कुल 3.4 बलियिन अमेरिकी डॉलर थी, जो राजस्व अंतर में योगदान करती है।

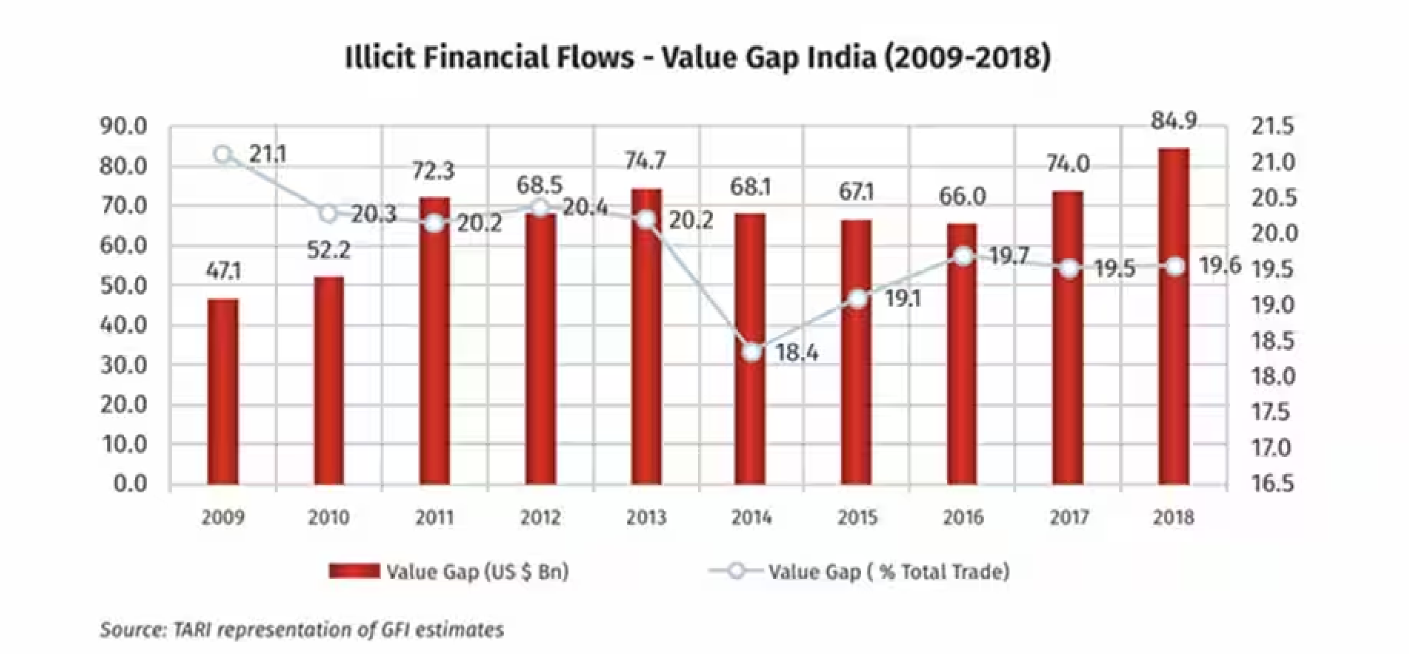

//

- **भारत में आतंक और अपराध:**
  - **आतंकवाद और अपराध** से नपिटने में भारत ने वर्ष 2021 में [क्रय शक्ति समता](#) **(Purchasing Power Parity- PPP)** पर लगभग 1170 बलियिन अमेरिकी डॉलर खर्च किये, जो देश के कुल [सकल घरेलू उत्पाद](#) (Gross Domestic Product- GDP) का लगभग 6% है।
    - **PPP वृहत आर्थिक विश्लेषण** द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मीट्रिक है जो **"बास्केट ऑफ गुड्स"** दृष्टिकोण के माध्यम से **विभिन्नि देशों की मुद्राओं** की तुलना करता है, जिससे उन्हें देशों के बीच आर्थिक उत्पादकता और जीवन स्तर की तुलना करने की अनुमति मिलती है।

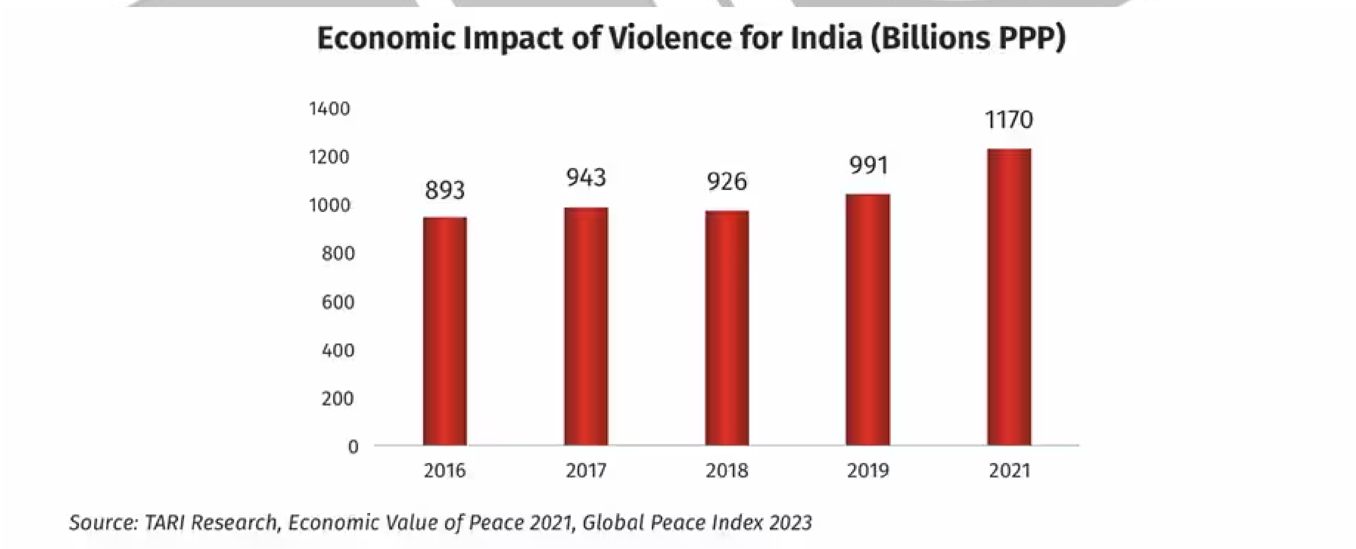

- **भारत में ड्रग अर्थव्यवस्था:**
  - [स्वर्णिम त्रिकोण/गोल्डन ट्रायंगल](#) **(म्याँमार, लाओस व थाईलैंड)** और [**स्वर्णिम अर्द्धचंद्र/गोल्डन क्रसिंट**](#)(अफगानिस्तान, पाकिस्तान व ईरान) सहित प्रमुख ड्रग उत्पादक क्षेत्रों के पास का भारतीय क्षेत्र उन गतिविधियों से जुड़ा हुआ है जहाँ **निषिद्ध पदार्थों का आवागमन तथा वितरण शामिल हो सकता है।**
  - भारत में अवैध नशीले ड्रग के व्यापार में वृद्धि देखी गई है, वर्ष 2006-2013 के दौरान 1,257 मामलों की तुलना में वर्ष 2014-2022 के दौरान नशीले ड्रग की ज़ब्ती के 3,172 मामले दर्ज़ किये गए।
  - बेंचमार्क औसत 5.4 की तुलना में 7.5 स्कोर के साथ [**कैनबिस**](#) की भारत में व्यापक उपस्थिति है। सिंथेटिक ड्रग व्यापार और हेरोइन व्यापार भी 6.5 के स्कोर के साथ बेंचमार्क औसत से अधिक है।

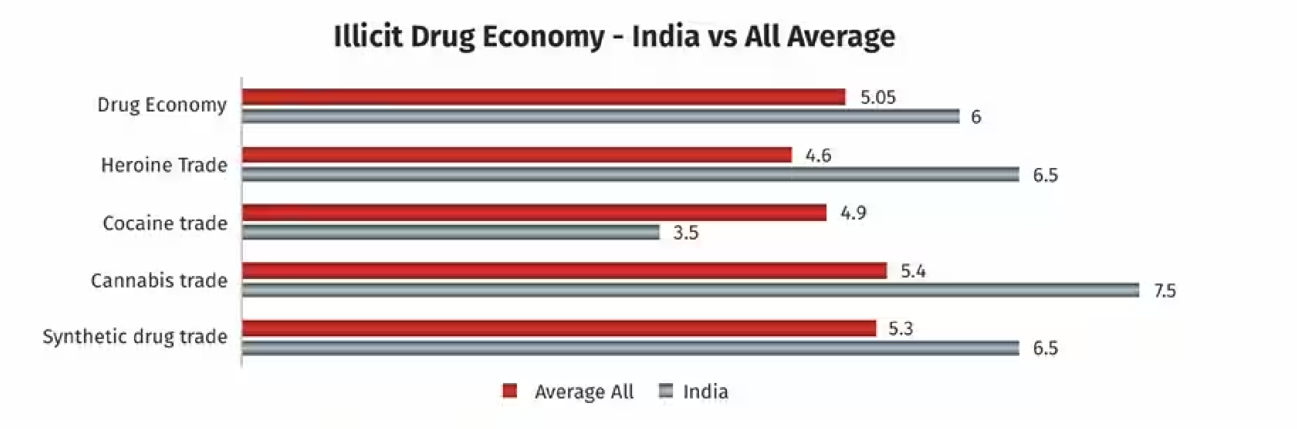

Source: TARI Research, GOCI

- **भारत में संगठति अपराध और अवैध अर्थव्यवस्था:**
  - भारत में संगठति अपराध करने वालों का कुल स्कोर **122 देशों के औसत बेंचमार्क 5.2** की तुलना में 4.3 है।

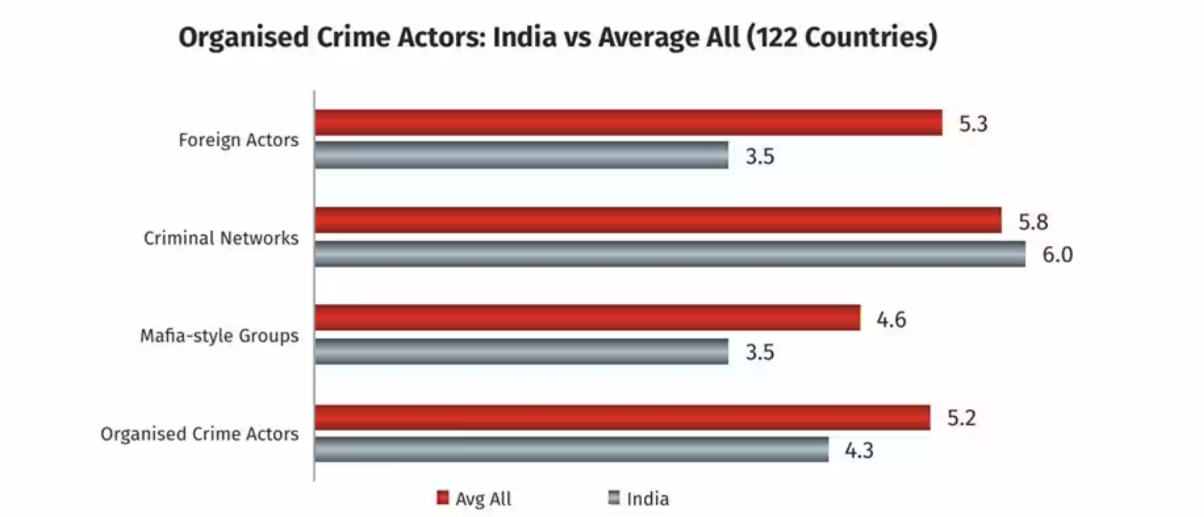

Source: TARI Research, GOCI 2021

  - हालाँकि 6 अंक के साथ आपराधकि नेटवर्क का भारत में बड़ा प्रभाव है, जो 122 देशों के औसत अंक 5.8 से अधकि है।
  - भारत में अवैध अर्थव्यवस्था का कुल स्कोर 6.3 है, जो 122 देशों में से 5 के औसत स्कोर से अधकि है।
    - इससे पता चलता है कयिद्यपि आपराधकि तत्त्व संख्या में कम कन्तिु व्यापक हैं और वभिन्नि प्रकार की गैरकानूनी गतविधियों में संलग्न हैं, जनिमें नशीली दवाओं की बक्रिी तथा मानव तस्करी के आलावा वन्यजीव उत्पादों में अवैध व्यापार शामलि हैं।
    - यह स्पष्ट वरिोधाभास भारत में आपराधकि नेटवर्क की प्रभावशीलता के लयि ज़म्मिेदार हो सकता है, जो उनकी कम संख्या के बावजूद पर्याप्त अवैध वत्तिीय प्रवाह करने में सक्षम बनाता है।

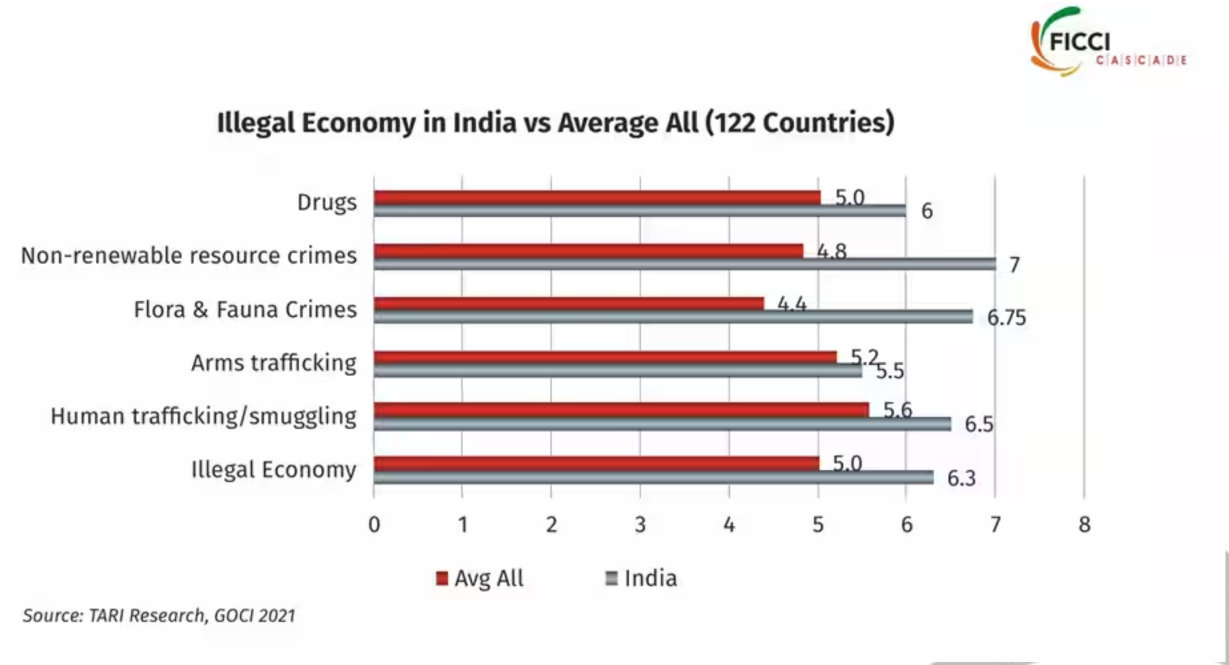

भारत में अवैध व्यापार से निपटने के लिये सरकार की पहलें:

- आतंकी वित्तपोषण और जाली मुद्रा (TFFC) सेल
- स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS) 1985
- नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR)
- नशीली दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कोष (NFCDA)
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA)
- PMLA (संशोधन) अधिनियम, 2012
- तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेरकर्ता (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018
- काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

[illegible]:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:(2019)

1. भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन [यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशनअगेंस्ट करप्शन (UNCAC)] का 'भूमि, समुद्र और वायुमार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल' होता है।
2. UNCAC अब तक का सबसे पहला विधितः बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार-विरोधी लिखित है।
3. राष्ट्र-पार संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन [यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल क्राइम (UNTOC) की विशिष्टता ऐसे एक विशिष्ट अध्याय का समावेशन है, जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना है, जिनसे वे अवैध तरीके से ले ली गई थीं।
4. मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय [यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC)] संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा UNCAC और UNTOC दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिये आधिदेशित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 2 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/illicit-trade-in-india